POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983)

ग्रा.ग./2012/अंक 12

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2012 मूल्य 50 पैसे

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन पत्रकारों को दिए जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है। इस बार का यह पुरस्कार 30 अक्टूबर 2012 को 'कट्स' द्वारा ग्रेनिर्का परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला के दौरान गोपाल शर्मा, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

उन्होंने वर्ष 2011 के लिए चयनित 'खाद्य सुरक्षा' विषय पर की गई उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए बाड़मेर जिले के पनावड़ा गांव निवासी स्वतंत्र पत्रकार चूना राम गोदारा को पुरस्कार स्वरूप 10 हजार रुपए की राशि का चैक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर 'ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार' से सम्मानित किया।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! बहुत अन्धेरा है, आओ कुछ दीप जलाएं! क्या करें, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बातें करते-करते अब शर्म महसूस होने लगी है। क्योंकि, हमारे कई राजनेता बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, जिनमें कई दिग्गज भी शामिल दिखते हैं।

इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर जब उंगलियां उठती हैं, तो इन राजनेताओं का व्यवहार निंदनीय हो जाता है। उनकी सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है। वे आम जन को भ्रमित करने के मकसद से ऊल-जलूल बयान देने लगते हैं।

चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उनकी पार्टी के अन्य साथी नेता भ्रष्टाचारी के बचाव के लिए आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। कुछ बड़े नेता चुप्पी भी साध लेते हैं, जैसे वे आरोपों के बारे में अनजान हो या सच्चाई को छिपाने की कोशिश में लगे हों।

पिछले दिनों अरविन्द केजरीवाल ने एक के बाद एक राजनीतिक दलों के ऐसे भ्रष्ट नेताओं और उनके काले कारनामों पर सवालों की जो बौछार लगाई, तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आज अन्ना हजारे हों या रामदेव या केजरीवाल, आम जन में भारतीय राजनीति में आई नैतिक गिरावट को उजागर करने में लगे हैं।

इससे लोग मानने लगे हैं कि नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं, उनमें जरूर कुछ सच्चाई है। लोगों का सवाल यह भी है कि क्या इनकी निष्पक्ष जांच हो सकेगी? क्योंकि, जिन पर आरोप लगे हैं वे देश की जनता को जवाब देने के बजाय आरोपों को निराधार बता कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।

वे यह भी नहीं समझ रहे कि इससे जनता में उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। जबकि एक न एक दिन जवाब देने के लिए उन्हें जनता की अदालत में आना होगा।

मिलावट की तो देना होगा जुर्माना और टांगना होगा बोर्ड

भीलवाड़ा जिले के मिलावट करते पकड़े गए दो दुकानदारों को एक साल तक दुकान के बाहर 2 गुना 3 फीट का बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर लिखा होगा – 'मैं मिलावटखोर हूं'

जन हित के मद्देनजर यह अनूठी सजा भीलवाड़ा जिले की एडीएम कोर्ट ने दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इन दोनों पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें बोर्ड पर जुर्माना लगने की सूचना भी लिखनी होगी। भीलवाड़ा में बाजार नं. 3 स्थित रामा स्वीट्स की दुकान पर मिलावटी मावा और कृषि उपज मंडी के पास स्थित शक्ति वारदाना भंडार के यहां मिलावटी तेल पाए जाने के मामले में जिले की एडीएम कोर्ट ने यह आदेश दिए। दोनों दुकानदारों पर दो-दो मामले बनाए गए थे। व्यापारियों ने कोर्ट में सब स्टैंडर्ड सामान बेचने की गलती मानी। कोर्ट ने रामा स्वीट के सुवालाल शर्मा पर दस हजार रुपए तथा शक्ति वारदाना भंडार के राकेश कुमार अग्रवाल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि उन्हें एक माह के भीतर कोर्ट में जमा करानी होगी।

उम्मीद की जाती है कि कोर्ट के इस फैसला से मिलावटखोरों में डर पैदा होगा। कोर्ट के इस फैसले को एक नजीर के रूप में भी देखा जा सकता है।

जनहित का फैसला

तमाम कानूनों के बाद भी मिलावट पर रोक नहीं लग पा रही है। न तो सरकारें संजिदा है और न ही वे अफसर जिनकी जिम्मेदारी मिलावट रोकने की है। कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मिलावटखोरों के लिए चेतावनी तो है ही सरकार व अफसरों के लिए सबक भी है।

टिकट बुक होने पर भी सीट नहीं देना रेलवे को महंगा पड़ा

उपभोक्ता शक्ति

जयपुर स्थित जगतपुरा रोड निवासी सुरेश चन्द मीणा व इन्द्रा बाजार के रामकिशोर शर्मा ने भारतीय रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर प्रथम में अलग-अलग परिवाद दायर किया। उन्होंने मंच को बताया कि रेलवे ने एक यात्री की सहायता करने के आशय से आरक्षण चार्ट में उनके नाम को काटकर उस पर हाथ से अन्य व्यक्तियों के नाम लिख, उन्हें सीट आवंटित कर दी। रेलवे अधिकारियों से उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो उनकी सुनवाई तक नहीं की गई। आखिर उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी।

मामले की सुनवाई पर मंच ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया कि रेलवे ने चार्ट में हाथ से नाम लिखकर अन्य व्यक्तियों को सीट आरक्षित की थी। मंच ने रेलवे को टिकट बुक होने पर भी सीट नहीं देने का दोषी माना। मंच ने भारतीय रेलवे के अध्यक्ष, उप रेलवे जयपुर मंडल के प्रबंधक और पश्चिमी रेलवे भोपाल मंडल के प्रबन्धक को संयुक्त या पृथक रूप से सुरेश चन्द मीणा एवं रामकिशोर शर्मा को दस-दस हजार रुपए मानसिक संताप की एवज में हर्जाना देने और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए परिवाद खर्च के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं।

खादी के नाम पर खुली लूट

राज्य सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत जयपुर स्थित लोकसेवा संस्थान खादी ग्रामोद्योग की ओर से खादी कलस्टर बस्सी से जुड़ी संस्था फागी द्वारा सूती एवं पोली के लिए निःशुल्क चरखे व करघे कातिनों को वितरित किए जाने थे। इनसे होने वाले उत्पाद को संस्थान द्वारा खरीद कर बेचा जाना था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस योजना में लाखों रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। ब्यूरो द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि बुनकरों को यह चरखे बांटे ही नहीं गए। जो चरखे व करघे बांटे गए उनके भी पैसे वसूल लिए गए। उन चरखों से फर्जी उत्पादन दिखाया गया। दूसरी जगहों से माल खरीदा गया और उसे बेच कर व फर्जी बिल लगाकर कई प्रकार से धांधलियां की गई।

ग्रामीण विकास के लिए नई योजना

राज्यों को ग्रामीण विकास में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार पहली बार 40 हजार करोड़ रुपए का एक लचीला कोष तैयार करने की योजना बना रही है। यह कोष राज्यों के लिए अगले साल से 12वीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक के लिए उपलब्ध रहेगा। इस कोष में केन्द्र सरकार की 70 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के लिए यह कोष अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध रहेगा। इस कोष से ग्रामीण विकास मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं या केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा।

मनरेगा में घटे काम मांगने वाले

प्रदेश में मनरेगा योजना में 100 दिन काम मांगने वाले परिवारों की संख्या घट रही है। चार साल पहले 26 लाख परिवारों ने 100 दिन का काम मांगा था, जबकि इस साल छह महीने बीतने के बाद 77 हजार लोगों ने ही काम मांगा है।

हाल यह है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के आधार पर नरेगा के पहले चरण में स्थान पाने वाले करौली व सिरोही जिले में ही इस साल गिनती के परिवारों को काम मिला है। राज्य का ग्रामीण विकास विभाग काम मांग पर आधारित होने का तर्क देकर गिरती संख्या पर जवाब देने से पल्ला झाड़ रहा है।

किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज

प्रदेश में 26 लाख किसानों को 9500 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरित किया जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 8 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण देने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर अब 9431 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

दुष्प्रचार से बिगड़ रही है देश की छवि

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार से देश की छवि बिगड़ रही है। इससे अधिकारियों का मनोबल भी गिर रहा है। यह बात उन्होंने सीबीआई और राज्यों के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के सम्मेलन में कही है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ज्यादातर बड़े मामले कारोबारी कंपनियों से जुड़े हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव किया जाएगा। घूस लेने को ही नहीं बल्कि घूस देने को भी भ्रष्टाचार की परिभाषा के दायरे में लाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में आधार कार्ड योजना को मजबूती से लागू किया जाएगा।

सरपंच पति की प्रथा पर लगाएं अंकुश

ग्रामीण महिलाओं को अपनी ताकत पहचान कर सरपंच पति की प्रथा पर अंकुश लगाना चाहिए। यह बात जयपुर जिला प्रमुख हजारीलाल नागर ने प्रिया संस्थान की ओर से राज्य संन्दर्भ केन्द्र में राजस्थान में जेंडर (लिंग) संबंधी मुद्दों पर पंचायतों का सशक्तिकरण के तहत जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही।

उन्होंने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत में खुद निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे महिला व पुरुष भेदभाव को समाप्त करने को बल मिलेगा।

महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय

राज्यपाल मार्गेट अल्वा का कहना है कि समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। संसद में महिला अधिकार और कानून की बात उठाई जाती है तो उनके साथी सांसद ही उनका विरोध करते हैं। बीकानेर में एक निजी कालेज के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता जताई है।

नष्ट हो रही है जैव विविधता

सामाजिक संगठनों ने आगाह किया है कि देश की आर्थिक नीतियां जैव विविधता और आजीविका को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रही है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 25 से भी ज्यादा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आर्थिक विकास की यह अंधी दौड़ आगे चल कर बहुत महंगी साबित होगी।

संगठनों के अनुसार तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की नीतियों के कारण भूमि, वन, नदियां, पहाड़, समुद्री तट और घास के मैदान नष्ट होते जा रहे हैं। इससे न केवल जीवजन्तुओं की संख्या घटती जा रही है बल्कि गरीबों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है।

राजनीति हुई दूषित

अरविन्द केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए, किन्तु वर्तमान में राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है कि वहां ईमानदारी पर चलने वालों के लिए स्थान बना पाना मुश्किल तो नहीं पर कठिन अवश्य है।

केजरीवाल व उनके साथियों के लिए आगे भी काफी चुनौतीपूर्ण समय आएगा। चूंकि भ्रष्टाचार के अलावा आरक्षण, बेरोजगारी और जातिवाद जैसे कई बड़े मुद्दों का सामना भी उनको करना होगा। उस समय उनके आज के साथी बिखर सकते हैं।

- राकेश कुमार परमार, धौलपुर

जागे विरोध करने की समझ

देश भ्रष्टाचार रूपी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा है। अरविन्द केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन देश के विकास को सही दिशा देने वाला कदम है। आज हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जन परेशान है। बावजूद इसके विरोध करने की समझ विकसित होने में समय लग रहा है।

केजरीवाल के विरोध के स्वर को सभी ओर से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि यह स्वर उनका ही नहीं आम जनता का भी है। लड़ाई आसान नहीं है और इसमें समय भी लगेगा, लेकिन एक दिन सफलता निश्चित है। भ्रष्टाचार रूपी अंधकार मिटेगा, बस सभी को अपने हिस्से की मशाल थामे चलना है।

-अंजू सिंह, जयपुर

अब एक रुपए में मिलेगा पौधा

राज्य सरकार ने वन नीति 2010 के अनुसार वन एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने व पौधरोपण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के मकसद से पौधों की विक्रय दरें घटा दी है। अब मात्र एक रुपए में एक पौधा देने का निर्णय लिया गया है। अब तक वन विभाग की नर्सरियों में बड़े पौधों की दर 5 रुपए से 70 रुपए तक थी।

इससे कई संस्थाएं व आम लोग चाह कर भी पौधारोपण नहीं कर पाते थे। अब वे कई प्रजाति के पौधे एक रुपए प्रति पौधे की दर से प्राप्त कर सकेंगे। जनभागीदारी से पौधे लगाने से प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा।

ग्राम सचिवालय पर रहेगी पैनी नजर

ग्रामीण इलाकों के लोगों की शिकायतें दूर करने के मकसद से चल रहे ग्राम सचिवालय पर जिला प्रशासन पैनी नजर रखेगा। सचिवालय ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देगा। इसमें आने वाली शिकायतें न केवल रिकार्ड की जाएंगी, बल्कि कर्मचारियों को उनके निस्तारण की जानकारी भी लोगों को देनी होगी। उपखण्ड अधिकारियों को सचिवालय का समग्र अधिकारी बनाया गया है।

जयपुर जिला कलक्टर टी. रविकान्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले की हर ग्राम पंचायत में माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को इसका आयोजन होगा। हर ग्राम सचिवालय में हर बार विशेष योजना पर अभियान चलाया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर